

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों के लिए प्रावधान

सरिता शर्मा, शोधार्थी, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

डॉ. देवेन्द्र कुमार अग्रवाल, शोध पर्यवेक्षक, (प्राचार्य, सौरभ कॉलेज ऑफ टीचर ट्रेनिंग खेड़ा, हिण्डौन सिटी)

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, भारत की शिक्षा प्रणाली को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप पुनर्गठित करने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह नीति इस विचार पर आधारित है कि कोई भी शिक्षा प्रणाली तब तक प्रभावी नहीं हो सकती जब तक कि उसमें कार्यरत शिक्षक प्रेरित, प्रशिक्षित, और समर्थ न हों। अतः इस नीति में शिक्षकों की भूमिका को केन्द्रीय स्थान प्रदान किया गया है। नीति में शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पेशेवर विकास, पदोन्नति, मूल्यांकन, कार्यस्वतंत्रता और तकनीकी सशक्तिकरण से संबंधित व्यापक और क्रांतिकारी प्रावधान किए गए हैं। प्रस्तुत लेख में इन प्रावधानों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए यह बताया गया है कि कैसे इन सुधारों के माध्यम से शिक्षक समुदाय को सशक्त बनाकर शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक सुधार लाया जा सकता है।

Keywords: NEP 2020, CPD, DIKSHA, SWAYAM

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी राष्ट्र की प्रगति की आधारशिला होती है और शिक्षक उस नींव को मजबूत करने वाले स्तंभ होते हैं। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए शिक्षकों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी है। पहले की नीतियों की तुलना में यह नीति शिक्षकों को केवल ज्ञान के संप्रेषक नहीं बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास के मार्गदर्शक के रूप में देखती है। इस लेख में हम NEP 2020 में शिक्षकों के लिए किए गए प्रमुख प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

1. शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता आधारित चयन

NEP 2020 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। इसमें निम्नलिखित पहलुओं को शामिल किया गया है:

- शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
- शिक्षकों की भर्ती में संचार कौशल, समर्पण, और शिक्षण के प्रति रुचि जैसे गुणों का भी मूल्यांकन किया जाएगा।
- साइकोमेट्रिक परीक्षण और साक्षात्कार आधारित मूल्यांकन को अपनाने का सुझाव।

2. चार वर्षीय समेकित बी.एड. पाठ्यक्रम की अनिवार्यता

NEP 2020 के अनुसार वर्ष 2030 तक चार वर्षीय समेकित बी.एड. (B.Ed.) डिग्री को न्यूनतम योग्यता मान्यता दी जाएगी। इसके अंतर्गत:

- विषयगत ज्ञान, शिक्षण विधियों और व्यावहारिक प्रशिक्षण को एकीकृत किया जाएगा।
- केवल मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों द्वारा यह पाठ्यक्रम संचालित किया जाएगा।
- मौजूदा अल्पकालिक और असंगठित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को समाप्त या समाहित किया जाएगा।

3. सतत व्यावसायिक विकास (CPD)

शिक्षकों की निरंतर उन्नति हेतु हर वर्ष न्यूनतम 50 घंटे का प्रशिक्षण अनिवार्य किया गया है। इसमें शामिल हैं:

- नवीन शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण।
- विषयगत अद्यतन ज्ञान।
- नेतृत्व कौशल और मूल्य-आधारित शिक्षा।
- DIKSHA, SWAYAM जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रशिक्षण सुलभ होंगे।

4. राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST) की स्थापना

NEP 2020 में शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (National Professional Standards for Teachers - NPST) निर्धारित करने का प्रावधान है, जो:

- शिक्षकों की जिम्मेदारियों, क्षमताओं और नैतिक आचरण को परिभाषित करेगा।

- पदोन्नति, प्रदर्शन मूल्यांकन और सेवा शर्तों का आधार बनेगा।
- 2022 तक इन मानकों को लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

5. करियर प्रबंधन एवं पदोन्नति की पारदर्शी प्रणाली

नीति में शिक्षकों के लिए योग्यता और प्रदर्शन आधारित पदोन्नति प्रणाली अपनाने की बात कही गई है:

- शिक्षक, मेंटर शिक्षक, मुख्य शिक्षक और शिक्षा प्रशिक्षक जैसे विभिन्न स्तरों तक उन्नति कर सकेंगे।
- शिक्षक की पेशेवर दक्षता, प्रशिक्षण सहभागिता, और विद्यार्थियों की प्रगति जैसे आधारों पर मूल्यांकन किया जाएगा।

6. शिक्षक की गरिमा और कार्यस्वतंत्रता

NEP 2020 के अनुसार शिक्षकों को उनकी शिक्षण प्रक्रिया में स्वायत्तता दी जानी चाहिए। साथ ही:

- शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यभार को न्यूनतम किया जाएगा।
- उन्हें पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षण योजना, और मूल्यांकन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाएगी।
- विद्यालय संकुल/क्लस्टर प्रणाली के अंतर्गत आपसी सहयोग और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. तकनीकी एकीकरण और डिजिटल सशक्तिकरण

नीति में शिक्षकों के लिए तकनीकी संसाधनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है:

- डिजिटल प्लेटफॉर्म (जैसे DIKSHA, SWAYAM) से ई-लर्निंग सामग्री की उपलब्धता।
- ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल को अपनाने की सिफारिश।
- शिक्षकों को AI, AR/VR, और स्मार्ट क्लासरूम तकनीकों का प्रशिक्षण।

8. परामर्श और मेंटरिंग व्यवस्था

शिक्षकों के लिए नीति में राष्ट्रीय शिक्षक परामर्श मिशन (National Mission for Mentoring) की स्थापना का प्रावधान है:

- सेवानिवृत्त शिक्षाविदों को मेंटर के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- शिक्षकों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और व्यावसायिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों की डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी।

9. ग्रामीण एवं वंचित क्षेत्रों के शिक्षकों के लिए विशेष उपाय

नीति यह भी सुनिश्चित करती है कि दूर-दराज और सामाजिक रूप से वंचित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हों:

- स्थानीय भाषा में प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे।
- कठिन क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता, आवास सुविधा, और स्थानांतरण में प्राथमिकता मिलेगी।
- स्थानीय नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि शिक्षक लंबे समय तक सेवा दे सकें।

10. शिक्षक शिक्षा संस्थानों का एकीकरण और सुदृढीकरण

NEP 2020 के तहत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणात्मक सुधार के लिए:

- सभी स्टैंडअलोन बी.एड. कॉलेजों को बहुविषयक विश्वविद्यालयों में समाहित किया जाएगा।
- DIETs, SCERTs, और NCERT की भूमिका को मजबूत किया जाएगा।
- शिक्षक शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालयों में स्थापित किया जाएगा जो उच्च स्तरीय शोध और प्रशिक्षण को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को शिक्षा प्रणाली के केंद्र में रखा गया है। यह नीति न केवल शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास करती है बल्कि उनके पेशेवर जीवन को गरिमा, स्वतंत्रता और नवाचार से भरपूर बनाना चाहती है। यदि इन प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो भारत का शिक्षण समुदाय वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और प्रेरणादायक समूह के रूप में उभर सकता है।

संदर्भ

1. Ministry of Education, Government of India (2020). National Education Policy 2020.

Retrieved from <https://www.education.gov.in>

2. NCERT (2021). Implementation Handbook for School Leaders.
3. UNESCO (2019). Teaching and Learning: Achieving Quality for All.
4. SCERT Delhi (2022). Teacher Professional Development Modules.
5. Raina, V. (2021). "Teachers at the Heart of Education Reform", Indian Journal of Education Policy, Vol 3, Issue 2.
6. Kumar, S. (2020). "Transforming Teacher Education through NEP 2020", Education Today, Vol 8, Issue 1.

